सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार की

महत्वाकांक्षी योजनाएं

"मेरे प्रिय प्रदेशवासियों,

राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर मैं, सबसे पहले आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं आज आप सभी के सुखद एवं मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। यह दिवस हमारी संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सरकार के अभूतपूर्व वित्तीय प्रबन्धन एवं विकास कार्यों को समर्पित है। राजस्थान निर्माण का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। पिछले 63 सालों में राजस्थान ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। राजस्थान कभी पिछड़ा प्रदेश कहलाता था। लेकिन आज अभूतपूर्व वित्तीय प्रबन्धन के कारण समय ने करवट ली है। हमने प्रदेश में घाटे के बजट की परम्परा को बदलकर सभी निर्धारित वित्तीय मानदण्डों को पूरा करते हुए लगातार चार सालों में राजस्व अधिशेष (रेवेन्यू सरप्लस) बजट प्रस्तुत करके नई मिसाल कायम की है। हमारे इस कुशल वित्तीय प्रबन्धन तथा आप सभी के आशीर्वाद, सहयोग एवं शुभकामनाओं से राज्य सरकार इन चार सालों में ऐतिहासिक फैसले लेकर 'मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा/जांच योजना', 'जननी शिशु सुरक्षा योजना', 'मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना', जयपुर में मेट्रो रेल, घाट की गूणी सुरंग परियोजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू करने में सफल हो सकी है। इससे प्रदेश के चहुंमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इन चार सालों के दौरान हम प्रदेश में हिंसा, तनाव की बजाय आपसी सद्भाव, स्नेह और विश्वास की सुदीर्घ परम्परा को पुनः मजबूत करने में सफल रहे हैं। इससे हमें विकास योजनाओं को गति प्रदान करने में कामयाबी मिली है।

यह हमारे कुशल वित्तीय प्रबन्धन का ही सकारात्मक परिणाम है कि हम बच्चों, छात्र समुदाय और युवाओं से लेकर वृद्धजनों सहित अनुसूचित जाति, जनजाति, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक, महिला वर्ग, विशेष योग्यजनों एवं कर्मचारियों के उत्थान के लिए लगातार ऐसी कारगर योजनाएं और फ्लैगशिप कार्यक्रम बनाकर उनका क्रियान्वयन कर सके हैं। इससे राजस्थान राज्य का वर्तमान ही नहीं, भविष्य भी सुनहरा और दीर्घकालीन परिणाम देने वाला बनेगा। मुझे गर्व है कि हमारे प्रयास से वित्तीय प्रबन्धन प्रभावी हुआ, जिसकी सराहना भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एवं सीएजी द्वारा भी की गयी है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं और आधारभूत सुविधाओं का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है, जिसकी केवल प्रदेश स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना हुई है। अविश्वसनीय तथ्य यह भी है कि मरु भूमि कहे जाने वाले राजस्थान को लगातार 2 वर्ष से 'कृषि कर्मण पुरस्कार' से नवाज़ा गया। प्रदेश में पहली बार शिक्षा, चिकित्सा, आवास तथा अन्य क्षेत्रों में अनूठी योजनाएं बनी, जिसका अन्य राज्य भी, अपने यहां लागू करने की दृष्टि से, अध्ययन कर रहे हैं। यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्राथमिकता वाले ऊर्जा तंत्र को मजबूत बनाने और वृहद पेयजल योजनाओं की भी सार्थक शुरुआत हो सकी है।

हमारे अथक प्रयासों और राजस्थान को तेज गति से आगे बढ़ाने, प्रदेशवासियों की सामाजिक-आर्थिक जीवन शैली में क्रांतिकारी बदलाव लाने एवं रोजगार के नये अवसर जुटाने की दृष्टि से बाड़मेर में रिफाइनरी और पेट्रो केमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए ऐतिहासिक फैसला संभव हो सका, जो हमारे उज्ज्वल भविष्य के दूरगामी विज़न को दर्शाता है।

राजस्थान में तेल, गैस और लिग्नाइट के अथाह भण्डार मिले हैं। देश के लगभग 20 से 25 प्रतिशत तेल का उत्पादन राजस्थान में हो रहा है एवं आने वाले वक्त में यह और भी बढ़ेगा। इसी तरह गैस के भण्डार मिलने से यहां गैस आधारित पावर प्लांट, खाद कारखाना इत्यादि भी लगाना सम्भव होगा। हम इस विज़न के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाले वक्त में भी, जो रेवेन्यू जनरेट होगी, इससे प्रदेश में समग्र विकास सम्भव होगा।

यह हमारे विज़न से ही संभव हुआ है कि हम प्रदेश को विकास की ओर तेजी से अग्रसर करने के साथ आमजन और युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं पर खरा उतर सके हैं। हमारे सारे फैसले और सारी योजनाएं इसी रूप में आपके सामने हैं। प्रकृति ने हमें तेल, गैस, सौर ऊर्जा और अन्य बहुमूल्य खनिज सम्पदाएं प्रदान की हैं, जिसके वैज्ञानिक दोहन से हमारी आने वाली कई पीढ़ियों के सुनहरे भविष्य का निर्माण होगा। मुझे खुशी है कि आपने इन सबका हमेशा हृदय से स्वागत किया है।

मैं, इस मौके पर आप सभी से विकास की इस रफ्तार को निरन्तर बनाए रखने और पूर्व की भांति आपके स्नेह, सद्भाव, सहयोग और समर्थन की अपील करता हूं। धन्यवाद, जयहिन्द।"

अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान

मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा/जांच योजना

राजकीय अस्पतालों में आने वाले अमीर-गरीब सभी के लिए मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना। उपलब्ध दवाइयों की संख्या 400 से बढ़ाकर 600 की जा रही है। 7 अप्रेल, 2013 से प्रारम्भ हो रही है 'मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना' के प्रथम चरण में मेडीकल कॉलेजों से संबद्ध, जिला एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में ईसीजी, एक्स-रे, सोनोग्राफी एवं अन्य आवश्यक सामान्य जांचें नि:शुल्क।

2 अक्टूबर, 2011 से लागू मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत प्रथम वर्ष में लगभग 7 करोड़ 63 लाख रोगी लाभान्वित। आउटडोर में लगभग 46 प्रतिशत तथा इंडोर में 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज।

मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना

गरीबी की रेखा से नीचे गुजर रहे परिवारों के लिए 2 रुपये प्रति किलोग्राम के स्थान पर अब 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा। राजब्राण्ड फोर्टिफाइड आटा 8.60 रुपये से घटाकर 5 रुपये किलो में उपलब्ध। चीनी की दर 13.50 रुपये के स्थान पर 10 रुपये प्रति किलोग्राम। योजना पर अब वार्षिक अनुदान 350 रुपये से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये।

10 मई, 2010 से लागू इस योजना के अन्तर्गत 38.83 लाख बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अंत्योदय परिवारों को 2 रुपये किलो की दर से प्रतिमाह 25 किलोग्राम गेहूँ वितरित कर लाभान्वित किया गया।

मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना

10 लाख ग्रामीण परिवारों के लिए स्थायी मकान के स्वप्न को साकार करने हेतु राज्य की सबसे बड़ी योजना। कुल व्यय 3,400 करोड़ रुपये। अब तक 4 लाख 43 हजार पात्र बीपीएल परिवारों को आवास हेतु वित्तीय सहायता दी जा चुकी है। सहायता राशि 50 हजार से बढ़ाकर 70 हजार रुपये प्रति इकाई की गई।

3 जून, 2011 से लागू इस योजना के प्रथम वर्ष में 2,75,700 आवास की स्वीकृति। 96,203 पूर्ण, 1,69,497 आवास अन्तिम चरण में। द्वितीय वर्ष में 2 लाख आवासों के लक्ष्य के मुकाबले 1,92,463 की स्वीकृति जारी।

मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना

पहली बार शहरी बीपीएल के लिए अभूतपूर्व राहत। 50 हजार लाभार्थियों को सहायता राशि का वितरण किया जा रहा है। पात्र प्रति परिवार को आवास निर्माण हेतु सहायता राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 70 हजार रुपये प्रति इकाई की गई।

राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना

योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को नि:शुल्क संस्थागत प्रसव सुविधा। 200 नई 'जननी एक्सप्रेस'। 108 एम्बुलेंस की संख्या में 100 की बढ़ोतरी। 1 अप्रेल, 2013 से 'मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना' लागू। 1-1 करोड़ रुपये की लागत में प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में लेबर रूम का उच्चीकरण एवं मरम्मत का कार्य।

12 सितम्बर, 2011 से लागू इस योजना में अब तक 10 लाख 47 हजार संस्थागत प्रसव हुए, 16 लाख 40 हजार महिलाओं एवं 3 लाख 16 हजार शिशुओं को नि:शुल्क दवा तथा 98 लाख महिलाओं एवं 85 हजार शिशुओं को नि:शुल्क जांच सुविधा।

मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष, राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष

बीपीएल परिवारों के मरीजों को राजकीय चिकित्सालयों में संपूर्ण इलाज नि:शुल्क उपलब्ध करवाने के साथ ही, अब हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग का इलाज चिन्हित निजी चिकित्सालयों में करवाने पर एक लाख रुपये तक की सहायता राशि।

1 जनवरी, 2009 में लागू इस योजना में 150 करोड़ रुपये के व्यय से 1.44 करोड़ रोगी लाभान्वित। मुख्यमंत्री सहायता कोष से 125.6 करोड़ रुपये के व्यय से 46 हजार रोगी लाभान्वित।

मुख्यमंत्री पशुधन नि:शुल्क दवा योजना

राज्य के 5.67 करोड़ पशुधन के लिए लोकप्रिय योजना। अब नि:शुल्क दवाओं को 87 से बढ़ाकर 110 किया जा रहा है। सभी 288 तहसीलों में एक-एक मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट शीघ्र। इस योजना के बेहतर संचालन हेतु पृथक से 'राजस्थान वेटरनरी सर्विस कॉरपोरेशन' स्थापित किया जाएगा।

15 अगस्त, 2012 से लागू इस योजना में अब तक 18.58 करोड़ रुपये व्यय से 70.31 लाख पशुओं का उपचार।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना

सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों में दूध की आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को अब राज्य सरकार द्वारा 2 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान। योजना पर वार्षिक 150 करोड़ रुपये का व्यय। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद पर 100 रुपये के स्थान पर 150 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस राशि का भुगतान व 20 लाख टन के स्थान पर 30 लाख टन गेहूं की खरीद की जाएगी।

राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास योजना

250 से 499 तक की आबादी वाले 2000 गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं, शेष 1 हजार 400 गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का कार्य 2 चरणों में। प्रथम चरण में 517 गांवों को जोड़ा जाएगा। 100 से 249 तक आबादी वाले गांवों को जोड़ने हेतु प्रथम चरण में 500 गांवों को 585 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों से जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना

देश में पहली बार लागू ऐसी बड़ी योजना, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर, समाज के सभी वर्ग के परिवारों के प्रभावशाली 1 लाख विद्यार्थियों (मेरिट के आधार पर) को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति। उच्च शिक्षा हेतु 1 लाख रुपये तक का ऋण लेकर समय पर भुगतान करने पर 5% राशि का ब्याज अनुदान राज्य सरकार द्वारा।

राजीव गांधी डिजीटल विद्यार्थी योजना

कक्षा 8वीं में दूसरे से ग्यारहवां स्थान प्राप्त करने वाले 3.5 लाख विद्यार्थियों को 6-6 हजार मूल्य के टेबलेट पीसी उपलब्ध कराए जाएंगे। कक्षा 10 व 12 की मेरिट के प्रथम 10-10 हजार विद्यार्थियों को 14 इंच आकार के गुणवत्ता वाले लैपटॉप।

मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना

रोजगारपरक कैशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत 97 प्रकार के कौशल का प्रशिक्षण देकर रोजगार दिलवाने का कार्य आरम्भ। अब पात्रता हेतु परिवार की आय सीमा 2 लाख 50 हजार रुपये की गई। 2 लाख लोगों को स्वरोजगार हेतु रोजगार किट। 10 हजार युवाओं को ड्राइविंग एवं मोटर मैकेनिक का प्रशिक्षण।

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम, 2011

14 नवम्बर, 2011 से आरम्भ एक ऐसा अधिनियम जो जनता से जुड़े 18 विभागों की 153 सेवाओं को समयबद्ध व पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। अब तक 1 करोड़ 26 लाख प्रकरणों में सेवाएं प्रदान। लोक सेवा निदेशालय का गठन कर क्रियाशील किया गया। एकीकृत कॉल सेन्टर की स्थापना जल्द की जा रही है।

सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012

आम आदमी की समस्याओं तथा अभाव अभियोगों पर उनके अपने क्षेत्र में ही एक निश्चित समय सीमा में सुनवाई का अधिकार। अब तक 12,546 प्रकरणों में से 11,100 प्रकरण निस्तारित। लोक सेवा निदेशालय का गठन कर क्रियाशील किया गया। एकीकृत कॉल सेन्टर की स्थापना जल्द की जा रही है।

वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना

वृद्धावस्था तता विधवा पेंशन योजना की पात्रता हेतु 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुत्र नहीं होने की शर्त समाप्त। 75 वर्ष से आयु के वृद्ध, विशेष योग्यजन एवं विधवाओं हेतु मासिक पेंशन 400 रुपये से 750 रुपये। इसके अन्तर्गत 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार। योजनान्तर्गत 12.74 लाख पात्र व्यक्ति लाभान्वित।

प्रभावी वित्तीय प्रबन्धन

- मार्च 2013 में भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2010-11 में राजस्थान की विकास दर 15.28 प्रतिशत के साथ देश में सर्वोच्च एवं सर्वाधिक रही।
- राजकोष से देनदारियों (Fiscal Laibilities) का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (राज्य की जीडीपी) की 25.6 प्रतिशत ही है, जो वर्ष 2007-08 में 39.6 प्रतिशत था।
- प्रति व्यक्ति आय में 13.66 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2010-11 में राजस्थान देश में प्रथम रहा।
- राजकोषीय घाटा वर्ष 2011-12 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (राज्य की जीडीपी) के अनुपात की निर्धारित सीमा 3 प्रतिशत के मुकाबले केवल 0.9 प्रतिशत रहा। वर्ष 2004-05 में यह अनुपात 4.8 प्रतिशत था।
- उत्कृष्ट राजकोषीय प्रबन्धन से राज्य के गत चार बजट में राजस्व अधिशेष (Surplus) रहा है।
- 11वीं पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान देश में अग्रणी राज्यों में।
- गत 4 वर्षों में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में अभूतपूर्व वृद्धि। लगातार 2 वर्षों से ''कृषि कर्मण पुरस्कार'' किसानों को समर्पित।
- राज्य के वित्तीय प्रबन्धन की माननीय प्रधानमंत्री महोदय डॉ. मनमोहन सिंह, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, 13वें वित्त आयोग एवं सीएजी द्वारा सराहना की गई है।

सबको स्वच्छ पेयजल - ऐतिहासिक अभियान

- 6,000 करोड़ रुपये की 39 पेयजल परियोजनाएं, आगामी 3 वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य। 3,200 करोड़ रूपये की 24 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ।
- 32,554 गांव व ढाणियों एवं 7,162 अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों को निर्धारित पेयजल योजनाओं से लाभान्वित किया।
- भीलवाड़ा में चम्बल का पानी उपलब्ध कराने के लिए 728 करोड़ रुपये की योजना का कार्य प्रारम्भ।
- इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से नागौर पेयजल परियोजना के लिए 2,938 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत।
- नागौर जिले की नावां तहसील, नागौर लिफ्ट परियोजना फेज-द्वितीय व चम्बल से बूंदी शहर की पेयजल परियोजना पर कार्य आरम्भ।
- 688 करोड़ रुपये की बाड़मेर पेयजल परियोजना का लोकार्पण कर बाड़मेर शहर के 691 गांवों को पेयजल आपूर्ति।

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में स्वर्णिम विकास

- जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन एवं अन्य योजनाओं में अब तक 915 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा। अब तक 276 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ।
- 20 हजार सोलर घरेलू प्रकाश संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। एक लाख से ज्यादा सोलर घरेलू प्रकाश संयंत्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जा चुके हैं। वर्तमान में भड़ला, जोधपुर में सोलर पार्क की स्थापना का कार्य प्रगतिरत है।
- जोधपुर, जयपुर,अजमेर शहर में 'रूफ-टॉप पॉवर जेनरेशन स्कीम' लागू कर, सोलर सिटी के रुप में विकसित किया जाएगा।

रिफाइनरी से बदलेगी राजस्थान की तस्वीर और तक़दीर

बाड़मेर में रिफाइनरी-कम-पेट्रोकैमिकल कॉम्पलेक्स

बीते 4 वर्षों में राजस्थान सरकार के प्रयासों तथा केन्द्र सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के परिणामस्वरूप हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र में रिफाइनरी स्थापित करने का निर्णय लिया। सरकार की दूरगामी सोच से प्रदेश एक सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहा है। रिफाइनरी की स्थापना से पेट्रोकेमिकल, पेट्रो इंजीनियरिंग और अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों में अनेक नये उद्योग भी स्थापित होंगे। इस उपक्रम से लाखों लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। विश्वास है कि यह रिफाइनरी प्रदेश के विकास एवं खुशहाली की दिशा में युग परिवर्तन का कदम साबित होगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर राजस्थान की ओर से माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, माननीय यूपीए अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गाँधी, माननीय केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री डॉ. एम. वीरप्पा मोइली तथा उन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जिनके नेतृत्व एवं सहयोग से यह सपना साकार हुआ। सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।

–अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री

- राजस्थान सरकार और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. के बीच राज्य के बाड़मेर जिले में 9 एमएमटीपीए की अत्याधुनिक रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल संकुल स्थापित करने के लिए केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री डॉ. एम. वीरप्पा मोइली, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत एवं केन्द्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री श्रीमती पनबाका लक्ष्मी की उपस्थिति में 14 मार्च 2013 को जयपुर में राज्य के खान एवं पेट्रोलियम विभाग के शासन सचिव श्री सुधांशु पंत तथा एचपीसीएल के निदेशक (रिफाइनरी) श्री के. मुरली ने एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए।
- मंगला ऑयल फील्ड, बाड़मेर भारत का सबसे बड़ा तटवर्ती हाइड्रोकार्बन क्षेत्र है। इस रिफाइनरी की स्थापना पर लगभग 37,230 करोड़ रुपये के भारी निवेश से 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। उत्पादन 90 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष होगा। वर्ष 2016-17 तक इस परियोजना को पूरा कर लिया जाएगा। इससे पेट्रोलियम के साथ ही टैक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, प्लास्टिक एवं अन्य सेवा क्षेत्र के उद्योग भी पनपेंगे जिससे राजस्थान में खुशहाली आएगी।
- राजस्थान सरकार की अंश पूंजी में हिस्सेदारी। 15 वर्षों तक राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 3,736 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण।

पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ, बेटी बचाओ

–अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री

सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर द्वारा प्रकाशित एवं मै. प्रिन्ट 'ओ' लैण्ड, जयपुर द्वारा मुद्रित • मार्च, 2013/ प्रतियां 50, 000